दैनिक जागरण

संवेदना मनुष्य के अंत:करण की गहन और मौन अभिव्यक्ति है

पाक को सख्त संदेश

अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर में हर दिन सुधरते हालात के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह यह संकेत दिया कि अगर आवश्यकता हुई तो भारत नाभिकीय हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने के अपने सिद्धांत पर फिर से विचार कर सकता है उसका संदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी सुना चाहिए और वहां की सेना को भी। कश्मीर के मामले में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पूरी तरह अलग-थलग पड़ चुके इमरान खान को अब यह सच्चाई समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि परमाणु हथियारों के सहारे ब्लैकमेलिंग की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह गई है और वह बार-बार युद्ध का जो डर दिखाते रहते हैं वह उनके खोखलेपन को ही उजागर करता है। इमरान खान से भी अधिक पाकिस्तानी सेना को एक सेना के बल के रूप में अपने आचरण को सुधारना होगा। भारत ने शुरुआत से ही एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति का परिचय दिया है। जिम्मेदारी का यह भाव परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने के उसके संकल्प से ही परिलक्षित होता है। यह संकल्प अटूट है, लेकिन पाकिस्तानी शासन और सेना के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि अगर परिस्थितियों ने भारत को इस संकल्प से बाहर निकलने के लिए विवश किया तो वह ऐसा करने से हिचकिचाएगा नहीं।

भारत के खिलाफ आतंकवाद को छद्म युद्ध के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तानी सेना यह सहन नहीं कर पा रही है कि जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर के मोर्चे पर हर स्तर पर पराजित हो जाने के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के सिलसिले को तेज कर सकता है। इसके प्रति हर स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पड़ोसी देशों के साथ पूरी दुनिया को आश्वस्त किया कि भारत दक्षिण एशिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से कदम उठाए जाते रहेंगे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट में सैन्य कार्रवाई करके भारत अपने इरादे जता भी चुका है। समस्या यह है कि देश में अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो केवल सरकार की आलोचना करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में इस हद तक चला जाता है कि उसे आतंकवाद की पक्षधरता में भी कोई बुराई नजर नहीं आती। ऐसे ही तत्वों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी कश्मीर को लेकर गलत रिपोर्टिंग जारी रखे हुए है और पाकिस्तान का दुस्साहस भी बढ़ता है। यह आवश्यक है कि पाकिस्तान के साथ-साथ कश्मीर की अशांति के लिए जिम्मेदार ऐसे तत्वों को भी कोई कड़ा संदेश दिया जाए।

उम्मीद की किरण

उत्तराखंड सरकार ने देर से ही, पेयजल संकट से निपटने के लिए कुछ हटकर सोचने की पहल तो की है। प्रदेश के अर्द्धनगरीय इलाकों के लिए अलग पेयजल नीति की कवायद को इससे जोड़ा जा रहा है। दरअसल ये इलाके नगर निकायों से सटे हैं और वर्तमान में शहरी क्षेत्रों का स्वरूप ले चुके हैं। इनमें आधारभूत सुविधाओं के विकास में बजट की कमी आड़े आ रही है। पेयजल भी इसमें एक है। आलम यह कि यहां लोगों को जरूरतभर का पानी भी मयस्सर नहीं है। जो उपलब्ध भी है, उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। इनके लिए अलग से पेयजल नीति की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने पिछले दिनों ऐसे इलाकों को पेयजल संकट से निजात दिलाने की कसरत शुरू की, जो अब आगे बढ़ी है। दो रोज पहले हुए राज्य कैबिनेट ने इस पर बड़ा फैसला किया है। अर्द्धनगरीय शहरों में पेयजल संकट से निपटने के लिए 975 करोड़ रुपये की योजना पर मुहर लगाई गई है। विश्व बैंक की मदद से यह योजना वर्ष 2023 तक पूरी की जानी है। योजना पर 780 करोड़ रुपये विश्व बैंक खर्च करेगा, जबकि राज्यांश के रूप में 195 करोड़ रुपये राज्य सरकार को जुटाने हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले तीन-चार सालों के भीतर निकायों की सीमा से लगे इन इलाकों में पानी का संकट काफी हद तक हल हो जाएगा। हालांकि पेयजल की चुनौती सरकार के सामने फिर भी बनी रहेगा। चूंकि यह समस्या केवल इन्हीं क्षेत्रों नहीं, बल्कि समूचा प्रदेश इससे जूझ रहा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरे साल पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है। लोग एक अदद बाल्टी पानी के लिए रतजगा करते हैं। कुछेक इलाकों में खरीदकर पीने के पानी का इंतजाम करने की बातें भी सामने आती हैं। अब सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू किए हैं। निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास है, जो भविष्य के लिए उम्मीद जगाता दिख रहा है। सरकार को उन इलाकों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां पेयजल योजनाएं बदहाल हैं। खासकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अरसे से पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन नहीं हो पाया है लोगों को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। सही मायने में पेयजल को लेकर सरकार को सम्यक नीति पर विचार करना चाहिए। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो हालात यहां भी अच्छे नहीं हैं। बस, किसी तरह काम चल रहा है। आने वाले समय में यहां भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

निर्णायक रक्षा सुधार की पहल

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

सीडीएस की नियुक्ति से जहां तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बेहतर होगा वहीं दुनिया भर में सामरिक मोर्चे पर आ रहे बदलावों से ताल मिलाने में भी सहूलियत होगी

स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत अहम घोषणा की। उन्होंने सैन्य बलों की क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति का एलान किया। उन्होंने कहा, 'हमारे सैन्य बल भारत का गौरव हैं। उनमें और बेहतर समन्वय के लिए मैं लाल किले से एक अहम घोषणा करना चाहता हूं कि अब भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होगा।' देश में फिलहाल यही व्यवस्था है जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ को चीफ्स ऑफ स्टाफ्स कमेटी यानी सीओएससी का दर्जा दिया जाता है। मगर यह कोई विशेष दायित्व नहीं, बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इसमें अमूमन कार्यकाल भी बहुत छोटा होता है। जैसे फिलहाल सीओएससी वायु सेना प्रमुख बीएस धनोआ ने 31 मई को यह पद संभाला था। वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद सबसे वरिष्ठ होने के नाते जनरल बिपिन रावत यह जिम्मा संभालेंगे, मगर वह भी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार देखा जाए तो स्थायी सीडीएस की नियुक्ति तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय की दृष्टि से एक बड़ी पहल है। यह बीते 72 वर्षों के दौरान हुआ एक निर्णायक रक्षा सुधार है। इससे दुनिया भर में सामरिक मोर्चे पर आ रहे बदलावों से ताल मिलाने में भी सहूलियत होगी। सीडीएस सैन्य आधुनिकीकरण, संचालन तैयारियों और युद्ध जैसे तमाम मसलों पर राजनीतिक नेतृत्व को सलाह देने वाला इकलौता सैन्य सलाहकार होगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसी तमाम आधुनिक सेनाओं में सीडीएस जैसी व्यवस्था है। हालांकि वहां उसका नाम अलग है। मोदी ने आगे कहा, 'भारत जिस तरह की सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है उन्हें देखते हुए समय आ गया है कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाया जाए। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की दिशा में सीडीएस वह तालमेल और सैन्य बलों को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करेगा।' बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट के जरिये कहा, 'तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और संचालन को सरल बनाने के लिए आवश्यक सुधार के रूप में सीडीएस भारत के सुरक्षा परिदृश्य पर बेहद सकारात्मक एवं दूरगामी प्रभाव डालेगा।'

सीडीएस के गठन के साथ ही तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान का रास्ता भी साफ होगा। इससे तीनों सेनाओं के लिए दीर्घावधिक योजनाएं, रक्षा उपकरण खरीद, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स में सही तालमेल बैठेगा। मोदी की घोषणा के बाद अब रक्षा मंत्रालय सीडीएस नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें उसके कार्यकाल और अन्य संबंधित मुद्दों को तय किया जाएगा। सीडीएस की बुनियादी भूमिका सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच संचालन समन्वय को बेहतर बनाने की होगी। उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखना होगा। इसके अस्तित्व में आने से भारतीय सुरक्षा बलों की क्षमताएं निश्चित रूप से और बेहतर होने जा रही हैं।

अवधेश राजपूत

स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारतीय सेना में कमांडर-इन-चीफ का पद हुआ करता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को हमेशा सैन्य तख्तापलट की आशंका सताती थी। इसलिए उन्होंने अपने शासन में इस पद पद को समाप्त करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सीओएसी की परंपरा शुरू की। मगर सीडीएस की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जनरल मानेक शॉ को सीडीएस बनाना चाहती थीं, लेकिन नौकरशाही के अलावा वायु सेना और नौ सेना की कुछ आपत्तियों के चलते वह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया।

सीडीएस नियुक्ति की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी सिफारिश मंत्रियों के एक समूह यानी जीओएम ने की थी। इस मंत्री समूह का गठन कारगिल समीक्षा समिति के निष्कर्षों की पड़ताल करने के लिए किया गया था। भारतीय सामरिक रणनीति के पितामह माने जाने वाले के. सुब्रमण्यम कारगिल समीक्षा समिति के प्रमुख थे। मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हीं के पुत्र हैं। मई 2001 में तत्कालीन गृह मंत्री के नेतृत्व वाले जीओएम ने पूर्व रक्षा मंत्री अरुण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति पर इस विचार को आगे बढ़ाया। अरुण सिंह समिति ने 'भारत के सामरिक बलों की कमान के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही सरकार के लिए सैन्य सलाहकार की भूमिका के साथ' सीडीएस पद की संकल्पना पेश की। सीडीएस के उस स्वरूप का कुछ हल्का संस्करण 2012 में रक्षा सुधारों पर गठित नरेश चंद्रा टास्क फोर्स ने पेश किया जिसके आधार पर पर चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी चेयरमैन की व्यवस्था सामने आई। वर्ष 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर समिति ने एक बार फिर यही सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फैसले को अमल में लाने के लिए कोई समयसीमा तो नहीं दी है। न ही यह संकेत दिए गए कि यह कब से लागू होगा। फिर भी मौजूदा सरकार की चाल-ढाल को देखते हुए लगता है कि इसे जल्द ही अमलीजामा पहना दिया जाएगा। इसे अंतिम रूप देने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना होगा। मसलन सीडीएस का कार्यकाल कितना होगा या फिर उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी। क्या वह प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा या सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को? उसका मुख्यालय कहां होगा? प्रधानमंत्री कार्यालय में या रक्षा मंत्रालय में? सीडीएस के क्या अधिकार होंगे? क्या उसके पास बजट और संसाधन आवंटित करने की शक्ति होगी? या फिर वह केवल प्रतीकमात्र होगा? वरीयता अनुक्रम में उसका क्या स्थान होगा? सीडीएस की नियुक्ति से पहले सरकार को इन सभी सवालों के जवाब तलाशने होंगे।

अब अगला सवाल यही है कि सीडीएस कौन बनेगा? इस पर केवल एक स्पष्टता यही है कि वह चार सितारा जनरल होगा। क्या वह मौजूदा प्रमुखों में से कोई एक होगा। प्रधानमंत्री की घोषणा का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सेना और वायु सेना प्रमुख जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। फिलहाल एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ सबसे वरिष्ठ हैं और इसी आधार पर सीओएससी के चेयरमैन हैं। वह सितंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल रावत भी दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चूंकि सेना प्रमुख का दायरा तीनों सेनाओं में सबसे बड़ा है तो इस लिहाज से वह इसके लिए स्वाभाविक पसंद होने चाहिए। तीनों सेनाओं के प्रमुख को तीन वर्ष का नियत कार्यकाल या 62 वर्ष तक की सेवा अवधि मिलती है। ऐसे में अगर सरकार मौजूद प्रमुखों में से किसी को सीडीएस बनाती है तो इस पद के लिए सेवा अवधि की आयु सीमा भी 62 वर्ष से अधिक बढ़ानी होगी।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

लाल किले से मोदी के संदेश का मर्म

प्रदीप सिंह

ऐसी बातें वही कर सकता है जिसमें राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर देशहित में कुछ कहने, करने का माद्दा हो

संवाद की कला में निपुण हुए बिना कोई नेता महान नहीं बन सकता। महान नेताओं की खूबी होती है कि वे लोगों से जब भी बात करते हैं तो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। फिर उनकी बात से प्रेरित होकर लोग वह कर गुजरते हैं, जिसका उन्हें भी पूर्वानुमान नहीं होता। पिछले पांच साल में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करते हुए देख चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने पांच साल में इस देश के लोगों का व्यवहार ही नहीं, आदत भी बदल दी। देशवासियों के इस सहयोग के कारण प्रधानमंत्री इस समय आत्मविश्वास से लबरेज हैं। 73वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उनका संबोधन इसका प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने यूं तो लाल किले से बहुत-सी बातें कहीं, लेकिन आज जिक्र उन मुद्दों का जिनका तात्कालिक राजनीतिक नफा-नुकसान से कोई सीधा वास्ता नहीं है। ये मुद्दे किसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर नहीं उठाए गए हैं। ये मुद्दे ऐसे भी नहीं जिनका प्रभाव कुछ साल के लिए या सरकार के कार्यकाल तक के लिए हो। ऐसी बातें वही कर सकता है जिसमें दलगत राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर देशहित में कुछ कहने, करने का माद्दा हो। इस संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण, जलजीवन मिशन, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से परहेज, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी, जिलों के हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात, कृषि उत्पादों के निर्यात और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों का जिक्र जरूरी है।

सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। यह ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई राजनीतिक दल सपने में भी बोलने से डरता था। इस मुद्दे का जिक्र आते ही लोगों को आपातकाल के जमाने की ज्यादतियां याद आ जाती हैं, पर मोदी इससे डरकर चुप नहीं रहे। उन्होंने जनसंख्या विस्फोट की विकराल समस्या से लोगों को आगाह किया, पर वह यहीं नहीं रुके। कहा कि छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है, पर जो छोटा परिवार रखते हैं उन पर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का बोझ नहीं डाला जा सकता। हालांकि उन्होंने अभी इस संबंध में किसी कानून की बात नहीं की है, पर इस बात को उनके इस कथन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि हम समस्याओं को न पालते हैं, न टालते हैं। दरअसल दुनिया भर में यह माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी होनी चाहिए जिससे नई पीढ़ी लगभग उसी अनुपात में पुरानी पीढ़ी का स्थान ले सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होनी चाहिए। जबकि देश में यह दर 2.2 है। समस्या इस बात से और बढ़ जाती है कि सात राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम में यह ढाई से 3.2 तक है। इन सात राज्यों में देश की 45 फीसद आबादी बसती है। बढ़ती आबादी कई तरह के असंतुलन और चुनौतियां लेकर आती है।

पानी के संकट को उन्होंने जलजीवन मिशन का नाम दिया। देश के 75 फीसद लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। इस मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने महिलाओं की परेशानियों का जिक्र किया, जिन्हें कई-कई किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है। सरकार अगले पांच साल में जलजीवन मिशन पर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। जल संरक्षण से जल संचयन तक उन्होंने सभी चुनौतियों का जिक्र किया। इसी तरह प्रधानमंत्री ने एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक से परहेज करने की अपील की तो साथ ही किसानों से कहा कि अपने खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है, बल्कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा किसान अपने उत्पाद का निर्यातक क्यों नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि जिले के हस्तशिल्प उत्पाद के निर्यात का प्रयास होना चाहिए। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए मोदी ने लोगों से अपील कि वे 2022 तक देश के पंद्रह पर्यटन स्थलों पर जाएं। पर्यटन रोजगार का बड़ा जरिया है।

जनसंख्या और जलजीवन मिशन के अलावा बाकी लक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें आसानी से हासिल किया जा सकता है। इन मुद्दों पर कामयाबी उनकी अपील के असर पर निर्भर है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी को पांच साल से ज्यादा समय हो चुका है। वह 2014 में आए थे तो स्वयं को 'सिस्टम' से बाहर वाला बताकर बदलाव का वादा किया था। पांच साल बाद भी उन्होंने लाल किले से खुद को एक बार फिर बदलाव के वाहक के रूप में पेश किया है। बड़ी बात यह है कि लोगों को उनको इस भूमिका में स्वीकार करने से कोई गुरेज नहीं है। लोगों को मोदी पर यह भरोसा उनकी सरकार के पांच साल के काम से बना है। ऐसा भरोसा तभी बनता है जब लोगों को नेता की नीति ही नहीं नीयत पर भी यकीन हो। प्रधानमंत्री का यह आत्मविश्वास नए जनादेश और उनकी अपील को आगे बढ़कर जन अभियान बना देने के लोगों के संकल्प से उपजा है। प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से छठा संबोधन एक कुशल प्रशासक और समाज सुधारक का समन्वय था। साल 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से उनका सतत प्रयास रहा है कि समाज की शक्ति को जगाया जाए। भारतीय संस्कृति और परंपरा में सत्ता की शक्ति से ज्यादा अहमियत समाज की शक्ति की रही है। सत्ता पर आवश्यकता से ज्यादा निर्भरता किसी समाज और देश को बहुत आगे नहीं ले जा सकती। इस बात को प्रधानमंत्री अच्छी तरह समझते हैं।

उन्होंने पहले ही इस बात को समझ लिया था कि पिछली सरकारें अपेक्षित गति से देश का विकास नहीं कर पाईं तो इसका कारण केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव नहीं था। नेता की राजनीतिक इच्छाशक्ति तभी फलीभूत होती है जब उसे आम लोगों का समर्थन और सहभागिता मिले। पिछले पांच वर्षों में मोदी भारतीय समाज की इस शक्ति को जगाने में कामयाब रहे हैं। आम लोगों के साथ उनकी इस जुगलबंदी को उनके राजनीतिक विरोधी या तो भांप नहीं पाए या उस पर यकीन नहीं किया। नतीजा सबके सामने है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कार्य की सफलता

हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते है जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि ये आसानी से पूरे किए जा सकें जिससे सफलता हासिल हो सके। सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों न हो यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तब रास्ता सुगम हो जाता है।

प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी। उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी-भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। रेल गाड़ियों के परिचालन में अत्यंत भार के कारण इसके पहियों को प्रारंभिक गति देने में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये एक बार घूम जाते हैं तब ये स्वयं बलवान हो जाते हैं। पहियों और रेल के डिब्बे का वजन बहुत अधिक होने के कारण जब ये घूमने लगते हैं तब ये संवेग के कारण स्वयं शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में इसे दोबारा घुमाने में इंजन को पहले की अपेक्षा बहुत कम शक्ति लगानी पड़ती है। इसी प्रकार सफलता के पहियों का भी एक बार घूमना इसलिए कठिन होता है, क्योंकि ये रेल के समान भारी होते हैं, किंतु जब ये एक बार घूम जाते हैं तब इन्हें गति देने में ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है।

इस सफलता को और आगे बढ़ाने में उसकी मस्तिष्क की उत्साह रूपी शक्ति काम करने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को जब एक बार अपनी योग्यता पर विश्वास हो जाता है तब वह बड़े से बड़े कार्यों में हाथ डालने लगता है। फिर वह बड़े से बड़े कार्य को आसानी से संपादित करके सफलता प्राप्त करता रहता है।

वीके जायसवाल

सुशासन की राह में बाधाएं

रामकृष्ण जायसवाल

सुशासन की परिकल्पना तभी सिद्ध होती है जब वहां की सरकार और नागरिकों के बीच संबंध मधुर हों

सामान्यतः यह देखा जाता है कि लोगों को न तो लोक प्रशासन के बारे में ज्यादा पता होता है और न ही नवलोक प्रबंधन के। साथ ही सुशासन, लोकनीति और लोकरूचि का भी समुचित ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति तो मात्र यही सोचता है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे तथा उसे सामाजिक न्याय मिले और उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। यहां बताना उचित होगा कि अभिशासन सरकार की क्रिया है और सरकार एक संज्ञा है और सुशासन सरकार द्वारा किया जाने वाला कार्य है। सुशासन की अवधारणा का विकास कौटिल्य, अरस्तु तथा प्लेटो के दर्शन शास्त्र में देखा जा सकता है। राम राज्य के रूप में सुशासन की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से विकसित रही है, परंतु आधुनिक लोक प्रशासन की शब्दावली में यह शब्द 1990 के दशक में शामिल हुआ था। विश्व बैंक के एक दस्तावेज में सुशासन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया गया है जिससे शासन शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का प्रबंध करने के लिए किया जाता है। सुशासन की परिकल्पना तभी सिद्ध होती है जब केंद्र-राज्य, राज्य-राज्य, सरकार-बाजार, सरकार-नागरिकों के बीच संबंध मधुर हों। सामान्यतः प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता के बीच संबंध मजबूत होते हैं, लेकिन नागरिकों के साथ शासन व्यवस्था के संबंध उतने अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे में सुशासन की परिकल्पना का क्षरण हो जाता है। वैसे सरकार और नागरिक समाज तथा संगठनों के संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है।

भारत में नागरिक समाज का निर्माण न हो पाने के पीछे फैबियन समाजवादी नीति रही है। जिसका कारण यह है कि यहां आयकर 28 से 30 फीसद तक वसूला जाता है। यह तो कम है, इंदिरा गांधी सरकार ने तो अपने समय में 93 फीसद तक आयकर लगाए थे। यही कारण है कि आज देश में कर की चोरी चरम पर रही है। अगर भारत अमेरिका की तरह ही सभी को चार फीसद कर की सीमा में बांध दे तो निश्चित तौर पर सभी व्यक्ति खुशी के साथ कर जमा करेंगे, क्योंकि 28-30 प्रतिशत की जगह चार प्रतिशत कर देना सभी को मुनासिब होगा। और फिर सुशासन की अवधारणा को बल भी मिलेगा।

सुशासन एक पूंजीवादी अवधारणा है। यदि सुशासन लाना है तो सरकार के बोझ को कम करना होगा। निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना होगा। सुशासन का अर्थ यह भी है कि सरकारी कार्यों को जनता स्वयं अपना कार्य समझ कर करे। इससे सरकारी विभाग भी कम हो जाएंगे और भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी सुशासन मात्र कल्पना ही है, क्योंकि जनता-प्रशासन के बीच संबंध इस कदर मधुर नहीं हैं कि दोनों एक-दूसरे के क्रियाकलापों का सम्मान करें। इसी कारण सरकारी नियमों को लोग तोड़ने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। अतः देश में ऐसी स्थिति बनने के बाद ही पूर्ण सुशासन की उम्मीद की जा सकती है।

(लेखक शिक्षक हैं)

मेलबाक्स

सत्ता से जुड़ने की चाह

जुड़ाव की राजनीति के आगे बेबस विपक्ष शीर्षक से लिखे अपने लेख में बद्री नारायण ने लिखा है कि भाजपा अपने विरोधी दलों के जनाधार में सेंध लगा रही है। इसके लिए वह अपने विरोधी विचारों को आत्मसात करने से भी पीछे नहीं हट रही है। एक आम नागरिक के तौर पर मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने वैचारिक स्तर पर किसी तरह का लचीला रुख अपनाया है या उसका आयाम विस्तृत किया है, बल्कि वह अपने उग्र राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की नीति पर पहले की ही तरह मजबूती से खड़ी है। जहां तक उसका आधार बढ़ने की बात है तो इसकी सिर्फ एक ही वजह नजर आती है, वह आज के अधिकांश नेताओं में सत्ता सुख की चाह होना है। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व और अमित शाह जैसे कुशल रणनीतिकार हैं। ये दोनों राजनेता जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर हैं। इनके पास चुनाव जीतने की कला भी है और संसाधन भी। इनसे पार पाना कई विपक्षी दलों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में ज्यादातर चुनावों में भाजपा की जीत हो रही है और वह सत्ता में भागीदार बन रही है। आने वाले कई वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में भाजपा ही रहने वाली है। आज ज्यादातर लोग राजनीति में किसी विचारधारा के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अधिक से अधिक सत्ता का सुख भोगना ही उनकी मंशा है। इसी कारण दलबदल की समस्या भी इन दिनों गंभीर रूप से सामने आई है। ऐसे में भला कौन नेता सत्ता सुख से वंचित रहना चाहेगा। यही कारण है कि आजकल विपक्ष के ज्यादातर नेता भाजपा का रुख कर रहे हैं। कल अगर भाजपा कमजोर हुई और कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आने में सफल होती है तो ये नेता उसका दामन थामने से भी नहीं पीछे नहीं हटेंगे। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि सत्ता की चाह में भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, न कि उसकी विचारधारा को आत्मसात करने के कारण।

विवेक श्रीवास्तव, नई दिल्ली

विकास में बाधक

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिये अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने गांव, किसान, गरीब, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आदिवासी, जल संरक्षण, प्लास्टिक का अंत, पर्यटन को बढ़ावा, जम्मू कश्मीर का विकास, अंतरिक्ष तथा जनसंख्या विस्फोट जैसे विषयों से देश को अवगत कराया। हमारा देश निरंतर विकास की इबारत लिख रहा है। परंतु लगातार बढ़ती जनसंख्या सभी समस्याओं की जड़ है। जिस पर नियंत्रण पाए बिना प्रगति का सपना अधूरा ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान किया। आम नागरिकों को भी इस बात पर चिंतन करना चाहिए। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से परिवार नियोजन जैसे जागरूकता अभियान चलाती रही है, परंतु इसका बहुत कम असर देखने को मिला है। अब सरकार को एक ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। इस कानून के बनने से एक से दो दशक में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और देश स्वतः ही प्रगति पथ पर अग्रसर हो जाएगा।

hitender.dedha@gmail.com

महत्वपूर्ण है जनरल डिब्बा

पूरी दुनिया में भारतीय रेल का दूसरा व एशिया में पहला स्थान है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण रेलवे के सभी प्रयास यात्रियों के लिए कम पड़ जाते हैं। कह सकते हैं कि आम जनता या कमजोर वर्ग के लिए रेलवे भी सहूलियत देने में असमर्थ रही है। कालांतर में रेलवे में आम यात्रियों के लिए थर्ड क्लास की श्रेणी भी होती थी, लेकिन यहां भी रेलवे ने थर्ड क्लास को खत्म करने के नाम पर कमजोर वर्ग के साथ धोखा किया और रातों रात आधुनिक डिब्बों से थर्ड क्लास शब्द मिटवा कर साधारण, जनरल शब्द लिखवा दिया। रेलवे की इस घोषणा से जनता में अपार खुशी की लहर थी। वर्तमान में भारतीय रेल में यात्रियों के लिए कई क्लास होने पर भी कमाई के लिहाज से जनरल डिब्बों की अहमियत सबसे ज्यादा है, क्योंकि जनरल डिब्बों में क्षमता से चार गुना ज्यादा पैसेंजर होना आम बात है। त्योहारों के समय यह स्थिति और विकराल रूप धारण कर लेती है। रेलवे को चाहिए कि वह अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ आम लोगों को या गरीब लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक जनरल डिब्बे वाली ट्रेनों का संचालन करे।

प्रेमपाल सिंह, पलवल

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय 0120-4615800 E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं स हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय तिरिक्त।